	1990-91	1991-92	1992-93
वर्ष के आरम्भ में विचाराधीन आवेदन	18	19	21
प्राप्त आवेदन	61	61	54
जोड़	79	80	75
स्वीकृत/मंजूर	50	44	47
बंद किये गये/वापस लिये गये	10	15	14
विचाराधीन	19	21	14

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए औसतन लगभग तीन महीने का समय लिया जाता है।

(ख) और (ग) यूनिटों की संख्या और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मंजूर की गयी सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये)

	यूनिटों की संख्या	मंजूर की गयी रकम
1990-91	35	366.80
1991-92	29	263.30
1992-93	38	390.50

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के प्रावधानों तथा साथ ही साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 में किये गये प्रावधानों के अनुसार, यूनिटवार ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि किसी खास क्षेत्र में परियोजना का स्थान निर्धारण संबंधी निर्णय, उद्यमी पर छोड़ दिया जाता है जिसे क्रमशः राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत प्रोत्साहनों की उपलब्धता, कच्चे माल की सुलभता बाजार में पहुंच आदि के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। संस्थाएं, परियोजना की उपयुक्तता के लिहाज से परियोजना के स्थान का निर्धारण करती है। वित्तीय संस्थाओं का हमेशा यह प्रयास रहा है कि सभी अध्यक्ष परियोजनाओं का समर्थन किया जाये, भले ही वे किसी भी स्थान में स्थित हों।

Approval to Gujarat Development Bonds Scheme

82. SHRI ANANTRAY DEV SH ANKER DAVE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have approved the "Gujarat Development Bonds" Scheme submitted by Gujarat Government in November, 1992, which would increase the foreign exchange reserves of the country unconditionally and reduce dependence of SSP on budgetary allocation; and

(b) by when such Bonds would be allowed to be issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The Government of Gujarat had in November. 1992 proposed the issue of bonds to finance the Sardar Sarovar Project, relying on Government of India to absorb the foreign exchange risk. The proposal was, however, subsequently modified as a domestic public issue and the issue has already been completed.